Name of the State	1991 -92	1992-93	1993-94
14. Manipur	8.76	10.29	13.60
15. Meghalaya	10.61	12.64	16.00
16. Mizoram	3.68	4.38	5.88
17. Nagaland	4.90	5.83	7.41
18. Orissa	220.80	262.35	335.25
19. Punjab	87.13	103.32	132.77
20. Rajasthan	246.74	293.51	373.79
21. Sikkim.	1.51*	1.83*	2.14*
22. TamilNadu	404.72	481.19	613.73
23. Tripura	15.45	18.41	23.31
24. Uttar Pradesh	857.81	1015.59	1311.29
25 West Bengal	407.13	483.63	618.46
TOTAL . .	5105.84	6059.45	7771.27

NOTE : The share paid to Government of Sikkim was returned by the State Govt, stating that the enforcement of direct taxes to the State is pending.

कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क में वृद्धि

4415. **श्री रामजी लाल** : : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बजट में कच्चे माल पर उत्पाद शुल्क बढ़ा रही है और क्या इससे उद्योगों पर दोहरा कर-भार पड़ेगा तथा भारतीय उद्योग विफल होने लगेंगे;

(ख) क्या सरकार बजट पारित करते समय इस तरह के शुल्क को हटाने का विचार करती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इस बढ़े हुए भार से उद्योगों को राहत देने के लिए कोई अन्य योजना बनायी है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ में कच्ची सामग्री के लिए कोई विशिष्ट प्रविष्टि नहीं है । इस वर्ष के बजट में रसायन, लोहा और इस्पात जैसे कुछेक माल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाया गया है । सिन्थेटिक आर्गानिक डाई स्टफ, एल्युमिनियम आदि जैसे कुछेक माल के मामले में, उत्पाद शुल्क में कमी आई है । चूंकि कच्ची सामग्री पर अदा किया गया उत्पाद शुल्क अंतिम उत्पादों पर शुल्क की अदायगी के लिए सामान्यतया मॉडवेट क्रेडिट के रूप में उपलब्ध होता है अतः ऐसे माल पर शुल्क की दरों में परिवर्तन होने से, जिसे उद्योग द्वारा माल का आगे विनिर्माण करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब तक भारतीय उद्योगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक तैयार उत्पाद को शुल्क से छूट नहीं दी जाती है ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए, ये प्रश्न नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण

4416. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण कितना था और पिछले दो वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति औसत बैंक ऋण कितना रहा है; और

(ख) उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं और सरकार अपने प्रयासों में कितनी सफल रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि पिछले तीन वर्षों के लिए जनसंख्या अनन्तिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए प्रति व्यक्ति ऋण से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

अवधि	प्रति व्यक्ति ऋण (रुपए)
मार्च 1991	668
मार्च 1992	706
मार्च 1993	756